

खास-खाबरें

के. संजय मूर्ति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के. संजय मूर्ति ने मंगलवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हालांकि, इस मुलाकात का विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। राष्ट्रपति कार्यालय ने 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में इस मुलाकात की तस्वीर साझा की। बयान में लिखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के. संजय मूर्ति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की है।

विजनौर में 25 लाभार्थियों को वितरित किए गए एआई कार्ट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के विजनौर जनपद में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 अक्टूबर को 25 लाभार्थियों को एआई कार्ट वितरित किए गए। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पात्र महिला लाभार्थियों एवं अन्य पशुपालकों को एआई कार्ट तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. लोकेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन एवं पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित योजना का उद्देश्य पशुपालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उनकी आय में वृद्धि करना है। एआई कार्ट के माध्यम से लाभार्थी पशुपालन संबंधी सेवाओं को आगे बढ़ाकर अपनी आजीविका मजबूत कर सकेंगे। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इस प्रकार की योजनाओं से लाभार्थियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम के दौरान 25 लाभार्थियों को एआई कार्ट वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. लोकेश कुमार अग्रवाल,एन ईसीसी के अजीज सिंह, तथा सुभाष त्रिपाठी , संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ अमित दुबे ट्विनकैफे से जुड़े

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एआई आधारित डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म ट्विनकैफे ने राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ, लेखक और साइबर सुरक्षा मामलों के जानकार अमित दुबे को आसपास मॉन्टर और साइबर सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। डिजिटल पहचान, डीपफेक और साइबर अपराध से जुड़े बढ़ते खतरों के बीच कंपनी ने सुरक्षा और भरोसे को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया है। नोएडा में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में अमित दुबे के डिजिटल ट्विन की भी औपचारिक रूप से पेश किया गया, जो लोगों को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन देगा। नोएडा के सेक्टर-98 स्थित ट्विनकैफे कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अमित दुबे, ट्विनकैफे के प्रबंध निदेशक संदीप गोपाल तथा संस्थापक टीम के सदस्य एवं ब्रांड एवेंजलिस्ट तरुण सिंघल मौजूद रहे। ट्विनकैफे को पहले आस्कसिला के नाम से जाना जाता था। अब रीब्रांडिंग के बाद डिजिटल ट्विन तकनीक के जरिए लेखकों, विशेषज्ञों और रचनाकारों को उनके ज्ञान, व्यक्तित्व और अनुभव के आधार पर बड़े स्तर पर लोगों से जोड़ने का काम कर रहा है।

ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ावा, 73 स्थलों पर हुई सफाई

छठे विशेष अभियान के तहत 31 तक चलेंगी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने छठे विशेष अभियान के तहत अपने मुख्यालय और परिचालन क्षेत्रों में ई-कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत कंपनी के सभी प्रतिष्ठानों में व्यवस्थित अपशिष्ट संग्रह, पर्यावरण जागरूकता और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों में ई-कचरा संग्रह कियोस्क स्थापित किए गए हैं। इन कियोस्क के माध्यम से इस्तेमाल से बाहर हो चुकी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को

एकत्र कर अधिकृत रीसाइक्लिंग चैनलों के जरिए उनका जिम्मेदारीपूर्वक निपटान किया जा रहा है। कंपनी के मुख्यालय और परिचालन क्षेत्रों के कर्मचारी भी अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य स्वच्छता संबंधी प्रयासों को मजबूत करने के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदार प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।

कंपनी की ओर से कर्मचारियों और आसपास के समुदायों के बीच जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इनमें अनुचित ई-कचरा निपटान से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे और रसायनों के कारण हवा, मिट्टी तथा भूजल के दूषित होने के साथ मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर

शेयर बाजार में जोरदार उछाल

शेयर बाजार में जोरदार उछाल सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़ा

» **ट्रंप के ईरान पर हमला नहीं करने के बयान**

» **कर राहत की उम्मीद और आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को मिला सहारा**

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1,109 अंक उछलकर 73,034 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 359 अंक की बढ़त के साथ 22,722 के स्तर पर पहुंच गया। करों में राहत की उम्मीद, अमेरिका के ईरान पर हमला नहीं करने के बयान और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी भारतीय बाजार के लिए राहत लेकर आई। ट्रंप के बयान के बाद तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं कम हुईं। ब्रैंट क्रूड



का भाव 105 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, जबकि वेस्ट टेक्ससास इंटरमीडिएट क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए कीमतों में गिरावट

सकारात्मक मानी जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी खरीदारी देखने को मिली। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के सितंबर तिमाही के बेहतर नतीजों के बाद निफ्टी आईटी सूचकांक

चार प्रतिशत से अधिक चढ़ गया।

इस बीच, फ्यूजन सीएक्स का आर्थिक सार्वजनिक निर्गम मंगलवार को खुल गया। इसमें 16 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। कंपनी ने प्रति शेयर मूल्य दायरा 275 से 289 रुपये तय किया है। आवेदन के लिए एक लॉट में 51 शेयर रखे गए हैं। कंपनी इस निर्गम के जरिए 702 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली हालांकि चिंता का विषय बनी हुई है। बीते सात दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 24,342 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इसी अवधि में 23,088 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 548 अंक और निफ्टी 157 अंक गिरकर बंद हुए थे।

तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी

बाजार में तेजी की प्रमुख वजहों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान शामिल रहा। उन्होंने कहा कि तीन नवंबर को होने वाले मध्यरात्रि चुनाव से पहले अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रहने की खबरों से मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।

बाजार में सकारात्मक माहौल बना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर पर चर्चा करने की बात से भी बाजार में सकारात्मक माहौल बना। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है।

पीएफ ट्रस्टों को छूट नियमित कराने का मौका, 28 दिसंबर तक करना होगा आवेदन

ईपीएफओ ने देशव्यापी अभियान तेज किया, आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त ट्रस्टों को मिलेगा एकमुश्त लाभ

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि ट्रस्टों की छूट प्राप्त स्थिति को पिछली तारीख से नियमित कराने के लिए माफ़ी योजना 2026 के तहत देशव्यापी अभियान तेज कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्रतिष्ठानों को आवेदन जमा करने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

योजना के तहत छूट प्राप्त स्थिति को नियमित कराने के साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में निर्धारित न्यूनतम कर्मचारी संख्या, निधि की राशि और तीन वर्ष के अनुपालन संबंधी कुछ वैधानिक आवश्यकताओं से भी छूट का प्रावधान है। नियमितोकरण के बाद प्रतिष्ठानों को छूट प्राप्त या गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन करने का विकल्प भी मिलेगा।

जागरूकता बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ने भारतीय उद्योग परिषद, भारतीय सनदी लेखाकार



संस्थान और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सहित प्रमुख संगठनों के सहयोग से बैठकें और सेमिनार आयोजित किए हैं। सनदी लेखाकारों तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों को पात्र ट्रस्टों की

पहचान और सहायता के लिए लगाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यशालाएं, नियोक्ताओं से संपर्क और प्रक्रियागत जानकारी देने की पहल भी की जा रही है।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त ट्रस्ट

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 में शामिल माफ़ी योजना के प्रावधान 29 जून 2026 को अधिसूचित किए गए थे। इसके तहत ऐसे भविष्य निधि ट्रस्टों को अपनी छूट प्राप्त स्थिति नियमित कराने का एकमुश्त अवसर दिया गया है, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के तहत औपचारिक छूट आदेश जारी नहीं हुआ है। योजना के संचालन, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं से जुड़े दिशा-निर्देश 11 जुलाई 2026 को जारी किए गए थे। अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक लागू रहने वाली इस योजना की समय-सीमा नजदीक आने के कारण ईपीएफओ पात्र प्रतिष्ठानों से जल्द आवेदन करने की अपील कर रहा है।

भारत-चेक गणराज्य रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर भारत पर जोर



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कारेल हैबलिकेक के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता, संयुक्त रक्षा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में चेक गणराज्य के प्रथम उप प्रधानमंत्री और उद्योग एवं व्यापार मंत्री कारेल हैबलिकेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों

के बीच रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाओं की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने और संयुक्त रक्षा उपक्रमों में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

बैठक में भारत और चेक गणराज्य के बीच रक्षा उद्योग में सहयोग को और विस्तार देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अब तक हुए सहयोग और विभिन्न संयुक्त उपक्रमों की सफल स्थापना का स्वागत किया। साथ ही, दोनों देशों ने भारत-चेक संयुक्त रक्षा समिति के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को प्रोत्साहित करना है। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने शांति और सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

एआई से भाषा की बाधा दूर, नौ देशों के प्रतिनिधियों को मिला लाभ



नईदुनिया ब्यूरो, मसूरी: राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाषिणी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बहुभाषी तकनीक से भाषा की बाधा दूर करने में मदद मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने 12 से 23 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वास्तविक समय में बहुभाषी संवाद की सुविधा उपलब्ध कराई है।

शहरी सेवा वितरण विषय पर आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम में विभिन्न देशों के सिविल सेवक और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें पेरू, कंबोडिया, नाइजीरिया, केन्या, फिलिस्तीन, लेबनान, गैम्बिया, इक्वाडोर और स्पेन सहित कई देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और शहरी सेवाओं के वितरण से जुड़े अनुभवों तथा बेहतर कार्यप्रणालियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदान-प्रदान करना है। विदेश मंत्रालय की ओर से प्रायोजित यह कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत

» **स्वास्थ्य, कृषि और सार्वजनिक सेवाओं में भी उपयोग की संभावना**

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कर रहा है। कार्यक्रम के परिचयात्मक सत्र में भाषिणी के श्रुतलेख मंच के माध्यम से अंग्रेजी से स्पेनिश और स्पेनिश से अंग्रेजी में तत्काल अनुवाद की सुविधा दी गई। इससे अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले प्रतिनिधियों को एक-दूसरे की बात समझने, संवाद करने और प्रशिक्षण में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सहायता मिली। भाषिणी की टीम ने प्रतिभागियों को श्रुतलेख मंच के इस्तेमाल का तरीका बताया। साथ ही, उन्हें भाषिणी के बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र और स्वास्थ्य सेवा, वित्त, कृषि तथा सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में इसके संभावित उपयोगों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को रोजमर्रा के संवाद और डिजिटल बातचीत में भाषा संबंधी कठिनाइयां दूर करने के लिए भाषिणी मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। समापन यानी 23 अक्टूबर तक परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध रहेगा। यह पहल बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए अंतर-सांस्कृतिक संवाद मजबूत करने, ज्ञान के आदान-प्रदान को आसान बनाने और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण में समावेशी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

आरआईएनएल की जमीनों की ई-नीलामी को मिली थानदार प्रतिक्रिया

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एनएलएमसी ने मंगलवार को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का संचालन करने वाली कॉर्पोरेट इकाई आरआईएनएल से संबंधित प्रीमियम 150 भूखंडों की पहले दिन सफलतापूर्वक ई-नीलामी की। इससे सरकार को 366.33 करोड़ रुपये मिले।

वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के भूखंड की पहली डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन नीलामी से सफल बोलियों में पहले दिन 366.33 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जबकि 150 भूखंड बेचे गए हैं। यह प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग के तहत राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम ने किया है। मंत्रालय के अनुसार पहले चरण में प्रस्तुत भूखंडों में से 150 भूखंड सफलतापूर्वक बेचे गए। जिसमें 312.48 करोड़ रुपये की कुल आरक्षित मूल्य की अपेक्षा सफल बोली से 366.33 करोड़ रुपये का कुल मूल्य लगा।

10,000 एमएच बैटरी वाले 5 स्मार्टफोन, कीमत 30 हजार रुपये से शुरू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ने के साथ बैटरी क्षमता भी खरीदारों के लिए अहम हो गई है। वीडियो देखने, गेम खेलने, इंटरनेट चलाने और नेविगेशन के दौरान फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या से बचने के लिए बाजार में बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। अब 10,000 एमएच या इससे अधिक क्षमता वाली बैटरी के साथ कई मॉडल पेश किए गए हैं। इनमें रियलमी, पोको, वीवो और रेडमी के फोन शामिल हैं।

रियलमी पी4 पावर 5जी इस श्रेणी का एक विकल्प है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 29,999 रुपये है। इसमें 10,001 एमएच की बैटरी और 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है। फोन में 6.8 इंच की एमोलेड स्क्रीन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। रियलमी नॉर्जी पावर 5जी भी 10,001 एमएच बैटरी के साथ आता है।

आईएमएफ ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया

» **वर्ष 2026 और 2027 के लिए ज़ताया मजबूत वृद्धि का भरोसा**

» **घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को सहारा**

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में बढ़ोतरी करते हुए वर्ष 2026 और 2027, दोनों के लिए इसे सात प्रतिशत कर दिया है। अक्टूबर 2026 की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में संस्था ने मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन को भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमुख आधार बताया है।

अंतरराष्ट्रीय तनाव, वैश्विक

आर्थिक सुस्ती और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद भारत की विकास संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के लिए विकास दर का अनुमान जुलाई के आकलन से 0.6 प्रतिशत और अप्रैल के अनुमान से 0.5 प्रतिशत बढ़ाया है। वहीं, वर्ष 2027 के लिए अनुमान जुलाई की तुलना में 0.3 प्रतिशत और अप्रैल की तुलना में 0.5 प्रतिशत अधिक किया गया है।

भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सकारात्मक आकलन किया है। विश्व बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने भी भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर सात प्रतिशत के आसपास किया है।

खादी

खादी और ग्रामोद्योग को नई रफ्तार, बिक्री 1.87 लाख करोड़ रुपये के पार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: खादी और ग्रामोद्योग देश में ग्रामीण उद्यमिता, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शहद, हर्बल उत्पाद, वस्त्र, अगरबत्ती और केले के रेशे जैसे उत्पाद पारंपरिक कौशल को नए बाजारों से जोड़ रहे हैं। वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और विपणन सुविधाओं के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं में

खादी और स्थानीय उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को स्वदेशी वस्तुओं की खरीद के लिए प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 1.87 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2013-14 की तुलना में बिक्री में 501 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान उत्पादन 380 प्रतिशत बढ़कर 1,25,296 करोड़ रुपये हो गया, जबकि रोजगार 56 प्रतिशत बढ़कर 2.04 करोड़ तक पहुंच गया। सूत कातने वाले कारीगरों का पारिश्रमिक भी चार रुपये प्रति लच्छी से बढ़कर 15 रुपये हो गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग



के 35 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण और मोटर मरम्मत जैसे

क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में 79,682 लोगों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

खादी संस्थानों को 245 करोड़ रुपये की बाजार विकास सहायता दी

इनमें 47,382 महिलाएं शामिल थीं। खादी क्षेत्र के लगभग पांच लाख कारीगरों में 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से मार्च 2008 से अब तक लगभग 97.95 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 37,769 मशीनें, औजार और उपकरण वितरित किए गए। अब तक इस योजना के तहत 3.23 लाख से अधिक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। खादी संस्थानों को बाजार के अनुरूप उत्पाद विकसित करने और मूल्य संवर्धन में मदद देने के लिए खादी विकास योजना भी संचालित है। वर्ष 2024-25 में 1,097 खादी संस्थानों को 245 करोड़ रुपये की बाजार विकास सहायता दी गई, जिससे 1,45,484 कारीगर लाभान्वित हुए। ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना के तहत पात्र संस्थानों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ग्रामीण उद्यमों को डिजिटल बाजारों से जोड़ने के लिए खादी इंडिया का ऑनलाइन मंच भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त देशभर में बिक्री केंद्रों, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।